Vol 6 Issue 8 Sept 2016

ISSN No : 2230-7850

International Multidisciplinary Research Journal

Indian Streams Research Journal

Executive Editor
Ashok Yakkaldevi

Editor-in-Chief
H.N.Jagtap

Welcome to ISRJ

RNI MAHMUL/2011/38595 **ISSN No.2230-7850**

Indian Streams Research Journal is a multidisciplinary research journal, published monthly in English, Hindi & Marathi Language. All research papers submitted to the journal will be double - blind peer reviewed referred by members of the editorial board.Readers will include investigator in universities, research institutes government and industry with research interest in the general subjects.

Regional Editor

Dr. T. Manichander

Mr. Dikonda Govardhan Krushanahari
Professor and Researcher ,
Rayat shikshan sanstha's, Rajarshi Chhatrapati Shahu College, Kolhapur.

International Advisory Board

Kamani Perera
Regional Center For Strategic Studies, Sri Lanka

Janaki Sinnasamy
Librarian, University of Malaya

Romona Mihaila
Spiru Haret University, Romania

Delia Serbescu
Spiru Haret University, Bucharest, Romania

Anurag Misra
DBS College, Kanpur

Titus PopPhD, Partium Christian University, Oradea,Romania

Mohammad Hailat
Dept. of Mathematical Sciences, University of South Carolina Aiken

Abdullah Sabbagh
Engineering Studies, Sydney

Ecaterina Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest

Loredana Bosca
Spiru Haret University, Romania

Fabricio Moraes de Almeida
Federal University of Rondonia, Brazil

George - Calin SERITAN
Faculty of Philosophy and Socio-Political Sciences Al. I. Cuza University, Iasi

Hasan Baktir
English Language and Literature Department, Kayseri

Ghayoor Abbas Chotana
Dept of Chemistry, Lahore University of Management Sciences[PK]

Anna Maria Constantinovici
AL. I. Cuza University, Romania

Ilie Pintea,
Spiru Haret University, Romania

Xiaohua Yang
PhD, USA

.....More

Editorial Board

Pratap Vyamktrao Naikwade
ASP College Devrukh,Ratnagiri,MS India

R. R. Patil
Head Geology Department Solapur University,Solapur

Rama Bhosale
Prin. and Jt. Director Higher Education, Panvel

Salve R. N.
Department of Sociology, Shivaji University,Kolhapur

Govind P. Shinde
Bharati Vidyapeeth School of Distance Education Center, Navi Mumbai

Chakane Sanjay Dnyaneshwar
Arts, Science & Commerce College, Indapur, Pune

Awadhesh Kumar Shirotriya
Secretary,Play India Play,Meerut(U.P.)

Iresh Swami
Ex - VC. Solapur University, Solapur

N.S. Dhaygude
Ex. Prin. Dayanand College, Solapur

Narendra Kadu
Jt. Director Higher Education, Pune

K. M. Bhandarkar
Praful Patel College of Education, Gondia

Sonal Singh
Vikram University, Ujjain

G. P. Patankar
S. D. M. Degree College, Honavar, Karnataka

Maj. S. Bakhtiar Choudhary
Director,Hyderabad AP India.

S.Parvathi Devi
Ph.D.-University of Allahabad

Sonal Singh,
Vikram University, Ujjain

Rajendra Shendge
Director, B.C.U.D. Solapur University, Solapur

R. R. Yalikar
Director Managment Institute, Solapur

Umesh Rajderkar
Head Humanities & Social Science YCMOU,Nashik

S. R. Pandya
Head Education Dept. Mumbai University, Mumbai

Alka Darshan Shrivastava
Shaskiya Snatkottar Mahavidyalaya, Dhar

Rahul Shriram Sudke
Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore

S.KANNAN
Annamalai University,TN

Satish Kumar Kalhotra
Maulana Azad National Urdu University

Address:-Ashok Yakkaldevi 258/34, Raviwar Peth, Solapur - 413 005 Maharashtra, India
Cell : 9595 359 435, Ph No: 02172372010 Email: ayisrj@yahoo.in Website: www.isrj.org

ISSN: 2230-7850 Impact Factor :4.1625(UIF) Volume - 6 | Issue - 8 | September - 2016

Indian Streams Research Journal

ईराक का अध्ययन : भारत–ईराक संबंधों के परिपेक्ष्य में

डॉ. नेहा निरंजन

वरिष्ठ प्राध्यापक , राजनीति एवं लोक प्रशासन विभाग , डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर.

सारांश –

ईराक एशिया महाद्वीप का एक महत्वपूर्ण राष्ट्र है प्राचीन मेसोपोटामिया की सभ्यता का उदय यहीं पर हुआ, फारसी शासन के बाद सातवीं सदी के बाद यहाँ अरबो का प्रभुत्व हो गया। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद शुरू हुए शीतयुद्ध में ईराक, दो महाशक्तियों के बीच शक्ति परीक्षण का महत्वपूर्ण केन्द्र रहा था। २००३ में ईराक पर हुए अमरीकी आक्रमण के बाद ईराक में लोकतंत्र की स्थापना का जो प्रयास किया गया वह विश्व–राजनीति में बड़ा ही नाटकीय प्रयास रहा। क्योंकि साऊदी अरब के बाद ईराक विश्व में दूसरा सबसे बड़ा पेट्रोलियम तेल निर्यातक राष्ट्र है जिसके कारण न केवल एशियाई देशों की रूचि ईराक में है बल्कि अमरीका जैसी महाशक्ति भी इस क्षेत्र में अपने हितों की पूर्ति करना चाहता है। अतः लम्बें समय तक सद्दाम हुसैन के नेतृत्व में राजतंत्र के अंतर्गत शासित होने के बाद इस देश में प्रजातंत्र की स्थापना का और अमरीका के साथ–साथ भारत के लिए ईराक संबंधों की महत्ता का अध्ययन करना ही इस शोध पत्र का उद्देश्य है।

मुख्य बिन्दु – मैडेंट व्यवस्था, शीतयुद्ध, ईराक–ईरान युद्ध, कैम्पडेविड समझौता, कुवैत आक्रमण, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, एकध्रुवीय विश्व व्यवस्था, तेल कूटनीति, कर्बला।

प्रस्तावना

बदलते वैश्विक परिदृश्य में एशिया का महत्व बढ़ा है, नई विश्व व्यवस्था के अंतर्गत पश्चिम एशिया में भारत के हितों का विश्लेषण आवश्यक है क्योंकि पश्चिम एशिया ही भारत को यूरोप और अफ्रीका से जोड़ता है। पश्चिम एशिया ने केवल वर्तमान में अपितु सभ्यता के प्रारंभ से ही पूर्व एवं पश्चिम के राष्ट्रों को प्रभावित किया है। तेल कूटनीति का केन्द्र होने के कारण न केवल भारत जैसे विकासशील राष्ट्र अपितु अमरीका, चीन जैसे विकसित राष्ट्रों के लिए भी पश्चिम एशिया महत्व का क्षेत्र रहा है।

ईराक एशिया महाद्वीप में स्थित एक प्रजातांत्रिक देश है इसके दक्षिण में साऊदी अरब और कुवैत, पश्चिम में जार्डन और सीरिया, उत्तर में तुर्की और पूर्व में ईरान स्थित है। दक्षिण पश्चिम की दिशा में यह पारस की खाड़ी से जुड़ा है। दजला और फरात इसकी दो प्रमुख नदियां हैं इसके दोआवे में ही मेसोपोटामिया की सभ्यता का उदय हुआ था। लंबे समय तक निरंकुश राजतंत्र में रहते हुए और विकास करते हुए इस देश में कैसे प्रजातंत्र की स्थापना की गई और एशियाई राजनीति एवं महाशक्तियों के लिए उसकी महत्ता का अध्ययन निश्चय ही एक रोचक विषय है।

ईसा पूर्व छठी सदी से फारसी शासन में रहने के बाद (सातवी सदी तक) इस पर अरबों का प्रभुत्व हुआ। अरब शासन के समय यहां इस्लाम धर्म का प्रसार हुआ। तेरहवी सदी में मंगोल आक्रमण से बगदाद का पतन हो गया और उनके कुछ वर्षों बाद तुर्कों का प्रभुत्व यहां पर हो गया। प्रथम विश्वयुद्ध के पूर्व तक ईराक तुर्क साम्राज्य का एक अंग था, तुर्की के पतन के बाद इसे राष्ट्रसंघ की मैडेंट व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटेन के संरक्षण में रखा गया। १९२२ में मैडेंट की समाप्ति के उपरांत इराक एक स्वतंत्र राज्य बन गया।

१९३२ से १९५८ तक ईराक में संवैधानिक राजतंत्र रहा और हाशमी वंश के राजाओं ने वहां वंशानुक्रमानुगत शासन किया। १४ फरवरी १९५८ को शाह फैजल द्वितीय ने ईराक को जॉर्डन के साथ मिलाकर अरब संघ बनाया किंतु १४ जुलाई १९५८ को ईराक में सैनिक क्रांति हो गयी। शाह फैजल और तात्कालीन प्रधानमंत्री नूरी सईद मारे गये। तब अब्दुल करीम कासिम नये प्रधान मंत्री बने और ईराक को एक गणराज्य बना दिया गया लेकिन कासिम की सरकार को भी अनेक संकटों का सामना करना पड़ा जिसमें कुर्द की समस्या प्रमुख थी असल में उत्तरी ईराक में लगभग १० लाख कुर्द जाति के लोग रहते हैं जो कुर्दिस्तान के नाम से एक पूर्णतः स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना चाहते थे। १९६३ में उन्होंने सैनिक क्रांति

कर दी और कासिम की हत्या कर दी गई। जून १९६६ में ईराक की सरकार को झुकना पड़ा और उन्होंने कुर्द लोगों को स्वायत्त अधिकार देने की बात मान ली। इस तरह १९५८ में राजतंत्र के पतन के बाद लंबे समय तक ईराक में तानाशाही रही।

वर्ष १९७२ में ईराक ने तत्कालीन सोवियत संघ के साथ उस वक्त १५ वर्षों का सहयोग समझौता किया जब शीतयुद्ध अपनी चरम सीमा पर था। इराक ने अपनी उन तेल कंपनियों का भी राष्ट्रीकरण कर दिया जो पश्चिमी देशों को तब तक काफी सस्ती दरों पर तेल दे रही थी। वर्ष १९७३ में आया तेल संकट और उस वक्त जो भी फायदा हुआ उसका निवेश देश के उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य में किया गया। जल्दी ही जीवन स्तर के मामले में इराक का स्थान अरब जगत मे सबसे ऊपर के देशों में माना जाने लगा। धीरे–धीरे सद्दाम हुसैन ने सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत की और अपने रिश्तेदारों और सहयोगियों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त करते चले गए।

१९७९ में जनरल अलबकर से सद्दाम हुसैन ने कार्य भार संभाला और २२ जून १९८० को असेम्बली के चुनाव कराकर वहां के नागरिकों को लोकतांत्रिक अधिकारों के उपयोग का अवसर दिया।

ईराक–ईरान युद्ध

ईरान और ईराक मध्यपूर्व एशिया के दो प्रमुख देश है और रणनीति के आधार पर पश्चिमी एशिया में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ईराक जिसे प्रथम महायुद्ध तक मेसोपोटेमिया के नाम से जाना जाता था, उपजाऊ प्रदेश है, जो तिग्रन्स और यफ्रेट्स नदियों के बीच स्थित है इसके पूर्व में ईरान स्थित है यद्यपि दोनों ही देश मुस्लिम संप्रदायिवादी देश है किंतु मुस्लमानों के दोनों संप्रदाय सिया और सुन्नी में प्रारंभ से ही एक दूसरे के प्रति कटुता रही है। धर्मान्धता के कारण ईरान और ईराक हमेशा टकराव की स्थिति में रहे हैं। अतः मुस्लिम संप्रदायों के इसी पारस्परिक बैर, सीमा विवाद, कुर्द समस्या, त–अल–अरब जलमार्ग विवाद तथा मार्च १९७५ के अपमानजनक समझौते को पलट देने की ईराकी इच्छा के परिणामस्वरूप ही ईरान–ईराक युद्ध हुआ जो २२ सितम्बर १९८० से शुरू होकर ९ अगस्त १९८८ को विराम की स्थिति में आया। ईरान–ईराक युद्ध के उक्त कारणों के अतोगत्वा एक अन्य कारण, वैयक्तिक महत्वकांक्षाओं का टकराव भी था। असल में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में परिवर्तन के परिणामस्वरूप 'कैम्प डेविड' समझौते के बाद अरब जगत पर मिश्र का प्रभाव समाप्त हो गया ईरान के पतन के बाद न केवल पश्चिमी एशिया में अपितु समस्त मुस्लिम जगत मे एक बड़े नेता का आभाव सा प्रतीत होने लगा, उस समय ईराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन, जो एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे, उन्होंने इस क्षेत्र में अपनी धाक जमाने का प्रयास किया। सद्दाम हुसैन ने ईरान के अयातुल्ला खुमैनी के नेतृत्व में हुई ईरानी क्रांति को नकार दिया और उसे ईस्लाम विरोधी, फारसी नस्लवाद की संज्ञा दी साथ ही ईरान में खुमैनी विरोधी भावनाओं को भड़काना प्रारंभ कर दिया, इसके विपरीत दूसरी तरफ खुमैनी ने भी इस्लामी क्रांति का नारा देकर पूरे मुस्लिम क्षेत्र का एकमात्र नेता बनने का प्रयास किया।

शाह के पतन के बाद ईरानी क्रांति के परिणामस्वरूप ईरान में हिंसा और हत्याओं का दौर प्रारंभ हो गया था, चारों ओर अराजकता, धार्मिक कट्टरता, अवश्विास और अव्यवस्था व्याप्त थी, इन परिस्थितियों में ईराक का इरादा था कि ईरान को पराजित करके १९७५ के अपमान का बदला लिया जा सकता है और तब २२ सितंबर १९८० को ईराक द्वारा युद्ध प्रारंभ कर दिया गया। इस युद्ध में न केवल दोनों पक्षों को भयंकर आर्थिक क्षति उठानी पड़ी अपितु इसके राजनीतिक और आर्थिक परिणाम भी बहुत विनाशक सावित हुए। इस युद्ध में १० लाख से अधिक लोग मारे गये और दोनों देशों को ६० अरब डालर की क्षति हुई। प्रारंभ में युद्ध भूमि तक ही सीमित था परंतु समय के साथ साथ दोनों देशों ने इसमें वायु व नौ सेनाएं भी शामिल कर ली और बाद में तो प्रक्षेपास्त्रों का भी प्रयोग होने लगा जिसने रिहायशी क्षेत्रों में भीषण तबाही मचा दी। इस युद्ध के कारण दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं छिन्न–भिन्न हो गयी परिणामस्वरूप दोनों देशो के लोगों को भविष्य में वर्षों तक दरिद्रता में रहना पड़ा साथ ही अपने आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए महाशक्तियों पर निर्भर रहना पड़ा।

इस युद्ध के परिणामस्वरूप इस्लामिक राष्ट्र दो खेमों में बंट गये, युद्ध के कारण फारस की खाड़ी के क्षेत्र में तनाव में वृद्धि हुई, अरब इजरायल समस्या बढ़ी, तेल उत्पादन में निरंतर कमी हुई और अरब जगत दो गुटों में बंट गया। डॉ. वेदप्रताप वैदिक के शब्दों में ''इस युद्ध ने सारी अरब राजनीति को ही शीर्षासन करा दिया।''

ईराक और ईरान के बीच चल रहे इस लंबे संघर्ष को समाप्त कराने के लिये संयुक्त राष्ट्रसंघ, इस्लामी सम्मेलन, गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन, भारत, सोवियत संघ तथा विश्व के अन्य कई गुटनिरपेक्ष देश प्रयत्नशील रहे हैं। २५ फरवरी १९८६ को सुरक्षा परिषद ने एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पास करने की अपील की परंतु ईरान ने उसे ठुकरा दिया। कई सालों तक युद्ध विराम का आग्रह ठुकराने के पश्चात ईरान के नेता खोमैनी ने यू.एन.ओ. के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इस प्रस्ताव के अंतर्गत दोंनों देशों को फौरन युद्ध विराम लागू करने तथा अंतर्राराष्ट्रीय स्तर पर मान्य अपनी सीमाओं तक फौजें वापस हटाने तथा युद्ध बंदियों का विनिमय करने का प्रावधान था। इस तरह लंबे संघर्ष के बाद दोनों के मध्य युद्ध विराम हुआ।

१९९० में ईराक–ईरान युद्ध के बाद ईराक को आर्थिक आपदा का सामना करना पड़ा था। ईराक के दक्षिणी पड़ोसी एक छोटे देश कुवैत, जहां तेल का उत्पादन बढ़ गया था, ईराक के लिए अपने तेल राजस्व को अपेक्षाकृत नीचे कर दिया जबकि ईराकी सरकार ने यह आरोप लगाया कि कुवैत, अवैध रूप से साइलेन्ट ड्रिलिंग कर रहा है जिसे कुवैत ने खारिज कर दिया। अगस्त १९९० में ईराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण कर दिया गया। ईराकी सेना द्वारा तेजी से कुवैत पर कब्जा कर लिया गया और हुसैन ने घोषणा की कि अब कुवैत का स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है और वह ईराक का ही १९वां प्रांत बन गया। इस घोषणा के परिणामस्वरूप कई देशों से और यू.एन.ओ. से भारी आपत्तियां प्रकट की गईं। परिणामस्वरूप तब २ अगस्त १९९० को यू.एन.ओ. की सुरक्षा परिषद द्वारा ईराक पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव पारित किए गए साथ ही ईराक की कुवैत से तत्काल वापसी की मांग की गई। ईराक ने यू.एन.ओ. के इस निर्णय को मानने से इंकार कर दिया और १९९१ में यू.एन.ओ. की सुरक्षा परिषद् ने

सर्वसम्मति से ईराक के खिलाप सैन्य कार्यवाही के लिए मतदान किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्याय ७ के तहत संयुक्त राष्ट्र के चार्टर ६७८ में यह संकल्प अपनाया गया है कि, संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य राष्ट्र ''अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा'' को बहाल करने के लिए ''सभी आवश्यक साधनों'' का उपयोग करने के लिए अधिकृत हैं। फलस्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका की जिसके फारस की खाड़ी के क्षेत्र में तेल की आपूर्ति में भारी स्वार्थ निहित थे, ईराक और कुवैत के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन का नेतृत्व प्रदान किया गया।

संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक ध्रुवीय विश्व में नई विश्व व्यवस्था का नक्शा तैयार किया है उसके एजेण्डों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिन्दु में एक ईराक भी है। इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन का राजनीतिक अन्त एवं ईराक का पश्चिमी एशिया की मुख्य सैनिक शक्ति के रूप में खात्मा अमरीका के महत्वपूण उद्देश्यों से एक है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अमेरिका कूटनीतिक छल–कपट या सैनिक बल आदि के प्रयोग के माध्यम से अपने उद्देश्य की पूर्ति करने को तत्पर रहा है। यह कार्य अमेरिका मित्र राष्ट्र के सहयोग से करना चाहता था लेकिन यदि उसे मित्र राष्ट्रों का सहयोग नहीं भी मिला तो भी अपने बलबूते पर अपने कार्य को अंजाम देने के लिए अमरीका प्रारंभ से ही प्रयासरत रहा है।

इस कार्य के लिए अमरीका ने १९९६ सितंबर को दक्षिण ईराक के क्षेत्र तथा बगदाद पर ४४ ब्रूज मिसाइलें दागीं। मिसाइलों का यह आक्रमण बमवर्षक जलपोत से किया गया था। तत्पश्चात् उसने भोजन के लिए तेल समझौते पर रोक लगाई। एक फैसले के अनुसार इराक को तेल बेचना जनता के लिए भोजन व्यवस्था तथा दवाओं की खरीददारी करने का अधिकार दिया गया था लेकिन अमरीका द्वारा प्रतिबंध लगाये जाने से ईराकी जनता कुपोषण तथा बीमारियों की शिकार हो गई। इस अमानवीय कृत्य के लिए अमरीका के ही एक प्रोफेसर नोआम चोमस्की ने कहा कि, ''यह विधि का खुला उल्लंघन है। आगे उनका कहना था कि, विधि की दृष्टि से विचार करने पर तो अमरीका का कदम संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का जो कुछ खास परिस्थितियों को छोड़कर अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में शक्ति प्रयोग या उसके प्रयोग की धमकी को गैरकानूनी मानता है, खुला उल्लंघन है।''

इसके पीछे अमरीका के दो उद्देश्य थे एक तो राष्ट्रपति पद के निर्वाचन में क्लिंटन के पक्ष में माहौल तैयार हो, मिसाइल आक्रमण के जरिए क्लिंटन का उद्देश्य अमरीकी मतदाताओं के समक्ष अपनी छवि एक कठोर दृढ़निश्चयी व्यक्ति के रूप में पेश करना था। संकीर्ण चुनावी हितों के लिये यह ईराक की निरीह जनता की नीयत पर अमरीका के नागरिकों की भावनाओं और आवेश का सफल दोहन था। अमरीका का दूसरा उद्देश्य ईराकी राष्ट्रपति को चेतावनी देना था इसके साथ ही यह हमला अमरीका की बौखलाहट को सिद्ध करता था।

अमरीकी धमकियों और मिसाइलों के सामने न झुककर सद्दाम ने राष्ट्र की जनता को समझाकर अपनी शक्ति के सामाजिक आधार को व्यापक बनाने में सफलता प्राप्त की। अमरीकी आक्रमण का सद्दाम को सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि इस घटना से सद्दाम विरोधी दल में दरार पैदा हो गई। अभी तक जो क्षेत्रीय ताकतें आंख बंद करके सद्दाम के विरूद्ध अमरीका का साथ दे रही थी उनमें कुवैत को छोड़ अन्य ने इस अवसर पर अमरीका का साथ देने की अनिच्छा दिखाई। साम्राज्यवादी गुट की ताकतों में मात्र ब्रिटेन ही अमरीका का समर्थन कर रहा था। चीन तथा रूस ने भी अमरीका का खुलकर विरोध किया। इस अंतर्राष्ट्रीय रूझान के चलते भारत सरकार का स्वरूप भी विरोधी ही रहा। इस तरह ईराक पर मिसाइल आक्रमण के चलते संयुक्त राज्य अमरीका विश्व राजनीति में अलग–थलग पड़ गया।

२००१ में अमरीका पर हुए आतंकवादी आक्रमण के बाद जब अमरीका ने आतंकवाद विरोधी कार्यवाही की तो एक बार पुनः अमरीका को ईराक में हस्तक्षेप का मौका मिल गया। अंततः जुलाई २००३ में अमेरिका ने प्रजातंत्र की स्थापना और सद्दाम हुसैन के निरंकुश शासन को खत्म करने के लिए ईराक पर आक्रमण कर दिया।

ईराक पर थोपे गये अनुचित व अवैध युद्ध में विजयी होने पर भी संयुक्त राज्य अमेरिका अपने घोषित और उससे अलग वास्तविक लक्ष्यों में से किसी को भी प्राप्त नहीं कर सका है। २१वीं शताब्दी का ईराक युद्ध मानव समाज को नरसंहार के उन हथियारों से मुक्ति दिलाने के लिए लड़ा गया जो हथियार ईराक के पास थे ही नहीं। युद्ध को उचित ठहराने के लिए ईराक और आतंकवाद में सद्दाम तथा अलकायदा में सम्पर्क होने की बात कही गई जो उस समय झूठ थी। . . . युद्ध के उपरांत ईराक को प्रजातांत्रिक सरकार देने का वायदा किया थ । इराक में संविधान बनाम चुनाव का नाटक हुआ तथा अमरीका की कठपुतली सरकार भी आ गई किन्तु यथार्थ में ईराक में कोई भी पूर्ण प्रजातांत्रितक सरकार नहीं है, पूरा देश अभी भी अराजकता की गिरफ्त में है। अमरीका की सेनाएँ भले ही ईराक से चली गई लेकिन सिया और सुन्नियों के बीच संघर्ष आज भी जारी है।

भारत–ईराक संबंध

भारत और ईराक के बीच प्राचीनतम राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध रहे है। भारत से कपड़ा, खाद्यान्न, मसाले एवं अन्य उपयोगी वस्तुओं के साथ–साथ व्यक्ति भी ईराक में कार्य हेतु जाते थे। प्रतिवर्ष हजारों भारतीय करबला (कर्बला) में इमाम हुसैन और इमाम अब्बास के मकबरों और अब्दुल कादिर जिलानी के मकबरों का दीदार एवं माथा टेकने जाते हैं।

ईराक में युद्ध के बाद से भारत, आजाद, प्रजातांत्रिक और एकीकृत ईराक के निर्माण में अपना समर्थन देता रहा है। भारत ने राहत एवं आर्थिक पुर्नसंरचना के कार्य में ईराक की आवश्यकताओं हेतु प्रत्यक्ष रूप से एवं संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में सहयोग किया है। २००७ में ईराक में अमरीका समर्थित सरकार की स्थापना के बाद मई २००७ में ईराक के ऊर्जा कार्य उपप्रधानमंत्री हुसैन अल शरिस्तानी ने भारत की यात्रा की तथा ईराक के व्यापार मंत्रालय से सात सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने फरवरी २००६ में भारत का दौरा किया। इसी तरह जून २०१३ में भारतीय विदेश मंत्री श्री सलमान खुर्शीद ने भी ईराक का दौरा किया, बैठकों के दौरान राजनीतिक स्तर पर द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ बनाने पर सहमति व्यक्त की गई।

भारत और ईराक के बीच आर्थिक एवं व्यापारिक संबंधों में २००३ के समय में कमी आई। भारत थोक मात्रा में कच्चे तेल

का आयात करने के अलावा, ईराक से कच्चा ऊन एवं गंधक जैसी वस्तुओं का भी आयात करता है। वर्ष २०१३–१४ में ईराक से भारत का आयात १८५२०.८६ मिलियन अमरीकी डॉलर एवं निर्यात ६१८.०३ मिलियन अमरीकी डॉलर रहा।

भारत और ईराक के संबंधों की प्रगाढ़ता इस बात से स्पष्ट होता है कि आजादी के बाद सद्दाम हुसैन अकेले मुस्लिम राष्ट्राध्यक्ष थे जिन्होंने कश्मीर को भारत का अविभाज्य अंग माना और ऐलान भी किया। बावरी मस्जिद गिराए जाने पर जहाँ दुनिया में वबंडर मचा हुआ था वहाँ बगदाद शोत था, हुसैन का कहना था वह एक पुरानी इमारत गिरि है, यह भारत का मामला है। जबकि ढ़ाका में प्राचीन मंदिर गिरा दिया गया, हिन्दु महिलाओं के साथ वीभत्स जुल्म हुआ, इसी पूर्वी पाकिस्तान (बांग्लादेश) को भारतीय सेना, द्वारा मुक्त कराने पर बांग्लादेश को मान्यता में सद्दाम हुसैन सर्वप्रथम थे।

पोखरण द्वितीय १९९८ पर वाजपेयी सरकार को सर्वप्रथम सद्दाम हुसैन ने बधाई दी जबकि अनेक राष्ट्रों ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे। इसी तरह अनेक व्यापारियों और कर्मचारियों को ईराक में सुनहरे अवसर प्राप्त हुए है। यद्यपि सद्दाम हुसैन के समय में हुई प्रगति में अब गिरावट आ गयी है। एक तो अमरीका द्वारा थोपे गए युद्ध और बाद में आईएसआईएस की गतिविधियाँ एवं शिया–सुन्नी के आपसी विवाद ने ईराक की प्रगति को ध्वस्त कर दिया है।

जुलाई २०१६ में राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने ईराक की यात्रा की और इराकी प्रधानमंत्री नूरी कामिल अल मालिकी से मुलाकात की। उन्होंने दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए सांस्थानिक ढ़ांचा स्थापित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भारत ईराक के प्रगति और विकास में प्रतिबद्ध भागीदार है, ईराक के पुनर्निर्माण के प्रयासों में उसकी मदद करता रहेगा। राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने कहा कि ''भारत ईराक के साथ तेल अन्वेषण और पेट्रो–रसायन जैसे क्षेत्रों में समान भागीदार के तौर पर अपने संबंधों को और प्रगाढ़ता बनाने को उत्सुक है।''

२४ अगस्त २०१६ को पश्चिम एशिया के दौरे पर गए विदेश राज्यमंत्री एम.जे. अकबर सीरिया, लेबनान और ईराकी की यात्रा पर गए। अकबर की यात्रा की अहमियत इसलिए भी है क्योंकि भारत बदलते भूराजनीतिक महौल में खाड़ी देशों के साथ अपने रिश्तों को नया आयाम देने की कोशिश कर रहा है। ईराक में विदेश राज्यमंत्री एम.जे. अकबर ने वहाँ के विदेश मंत्री इब्राहिम अल इशाकेर अल इब्रहिम से मुलाकात की। भारत एवं ईराक के बीच बढ़ती वार्ताओं से, व्यापार, शिक्षा एवं विकास के विभिन्न क्षेत्रों में भारत को निवेश व कारोबार करने का न सिर्फ एक बड़ा बाजार मिलेगा बल्कि कश्मीर जैसे मुद्दों पर इनका समर्थन भी प्राप्त होगा।

केन्द्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद के अनुसार, इराक और भारत के संबंध मजबूत रहे है, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक हर क्षेत्र में इसे देखते हुए भारत को ईराक से मजबूत संबंध बनाए रखने की हर कोशिक करनी चाहिए। अमरीका के बाद भारत ईराकी तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीददार रहा है। भारत को ईराक से अपनी जरूरत का १९ प्रतिशत तेल मिलता है, साऊदी अरब के बाद दूसरा बड़ा निर्यातक है ईराक।

यद्यपि ईराक ने भारत का हर मंच से समर्थन किया है लेकिन अमरीकी युद्ध के दौरान भारत ने न तो अमरीका का समर्थन किया और न ही लंबे समय तक ईराक की यात्रा की। अतः लम्बे समय बाद अब पुनः दोनों देशों के संबंधों में प्रगाढ़ता हेतु पहले आर्थिक और सांस्कृतिक स्तर पर फिर राजनीतिक स्तर पर एवं फिर विश्वास बहाली करनी होगी, जिससे न केवल कश्मीर अपितु संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के प्रश्न पर भी ईराक का समर्थन प्राप्त हो सकेगा। निश्चय ही भारत और ईराक पहले की तरह ही सुदृढ़ मित्रता को कायम करने में कामयाब होंगे।

संदर्भ सूची –

१.भारतीय विदेश नीति, जे.एन. दीक्षित, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली २००८
२.अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, फ्रेडरिक एल. शूमां, मेकग्रा हिल बुक कम्पनी, न्यू यार्क
३.अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, लाल बहादुर प्रसाद, यूनिवर्सिटी प्रकाशन, २००६, नई दिल्ली।
४.अंतर्राष्ट्रीय संबंध वं विश्व राजनीति, पी.आर. भाटिया, अरूण प्रकाशन, ग्वालियर, १९८४
५.महामहिम राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी का वक्तव्य, Samacharjagat.com, Fostest Hindi News Website 14 July, 2016

Publish Research Article
International Level Multidisciplinary Research Journal
For All Subjects

Dear Sir/Mam,

We invite unpublished Research Paper,Summary of Research Project,Theses,Books and Book Review for publication,you will be pleased to know that our journals are

Associated and Indexed,India

- International Scientific Journal Consortium
- OPEN J-GATE

Associated and Indexed,USA

- Google Scholar
- EBSCO
- DOAJ
- Index Copernicus
- Publication Index
- Academic Journal Database
- Contemporary Research Index
- Academic Paper Databse
- Digital Journals Database
- Current Index to Scholarly Journals
- Elite Scientific Journal Archive
- Directory Of Academic Resources
- Scholar Journal Index
- Recent Science Index
- Scientific Resources Database
- Directory Of Research Journal Indexing

Indian Streams Research Journal
258/34 Raviwar Peth Solapur-413005,Maharashtra
Contact-9595359435
E-Mail-ayisrj@yahoo.in/ayisrj2011@gmail.com
Website : www.isrj.org